

रमेश पुत्र मांगीलाल जाति खारवाल निवासी उदई कलां तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
अपीलांटान

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
रेस्पोंडेडान

(अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु०न० 337/17 निर्णय दिनांक
9.2.18 एवं नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी मु०न० 55/15 निर्णय दिनांक 7.8.15)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की ओर से श्री शिवचरण शर्मा
2. रेस्पोंडेडान की ओर से पैरोकार सरकार



निर्णय

दिनांक 30.09.2019

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु०न० 337/17 निर्णय दिनांक 9.2.18 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 55/15 दिनांक 7.8.15 के विरुद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर में अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 7.8.15 के विरुद्ध प्रथम अपील इस आशय की पेश की थी कि ग्राम उदई कलां ए की आराजी ख०न० 1623 रकवा 0.02 है० गैर मुमकिन रास्ता पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर अपीलांट को भूमि से बेदखल करने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहाँ पेश की गई थी। अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की जाकर नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के निर्णय का यथावत रखने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेडान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस अपील में बताया कि दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरुद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। एक मात्र पटवारी

हल्का के बयान को आधार मानकर अपीलान्त का सजायाव किया है। जबकि पटवारी हल्का से अपीलार्थी को जिरह का अवसर नहीं मिला है। बिना जिरह के बयानों के आधार पर सिविल कारावास की सजा दिया जाना विधि विरुद्ध है। भूमि ख0न0 1623 रबा 0.02 वाके ग्राम उदेई कलां पर अपीलान्त का कोई कब्जा न तो पूर्व में था ना ही वर्तमान में है। विवादित आराजीयात से अपीलान्त का कोई सास्ता संबंध नहीं है। इसके बावजूद भी अपीलान्त के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त अशिक्षित गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है। जो पल्लेदारी का कार्य करके परिवार का पालना पोषण करता है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर दोनो अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को अपास्त फरमाया जावे।



सपो0 के अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस अपील में बताया कि अपीलान्त द्वारा ग्राम उदेई कलां की आराजी ख0न0 1623 रकबा 0.02 है0 गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण किये जाने के कारण ही पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91(3) की रिपोर्ट नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष पेश की गई है। अपीलान्त द्वारा तहत न्यायालय में उपस्थित होकर अतिक्रमण नहीं होने/हटा लेने का शपथ पत्र भी पेश किया गया था जिसकी जाँच पटवारी हल्का एवं नायब तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर की गई। जिस पर मौके पर अतिक्रमण पाया गया था। अपीलान्त द्वारा तहत न्यायालय में झूठा शपथ पत्र पेश कर न्यायालय को गुमराह किया गया है। अपीलान्त बार बार अतिक्रमण करने का आदि है। इस कारण ही पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमी रिपोर्ट नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष पेश की गई थी। अपीलान्त द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उसकी किस्म गैर मुमकिन रास्ता है जो आम जन के लोक प्रयोजन की भूमि है। गैर मुमकिन रास्ते के संबंध में आमजन की शिकायतें भी उच्चाधिकारियों को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार के अतिक्रमी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जो विधि अनुरूप है। यदि इस प्रकार के अतिक्रमियों की सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। अतः अपील खारिज फरमाई जाकर दोनो अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को यथावत रखा जावे।

28-6-19
समक्ष पेश की बहस अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरुद्ध नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष पेश करने पर नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्त को सुनवाई हेतु दिनांक 23.7.15 को नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 30.7.15 नियत की गई। जिसकी तामिल तामिल कुनिन्दा द्वारा अपीलार्थी के पुत्र द्वारा करवाई जाकर तामिली प्रति नायब तहसीलदार के समक्ष पेश की गई है। जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अतिक्रमण नहीं होने/हटा लेने का शपथ पत्र भी पेश किया गया है। जिसकी सम्यक जाँच स्वयं नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर की गई है जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा मौके से अपीलार्थी

द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के फसलस्वरूप ही अपीलार्थी के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी बार बार अतिक्रमण करने का कार्य आती है। विवादित आराजीयात की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। जो आम जन के आने जाने के कार्यों आती है। यदि इस प्रकार के अतिक्रमियों की सजा माफ कर दी जाती है तो ऐसे लोगों के कार्यों बुलन्द हो जावेगे। इस प्रकार हमारे मतानुसार अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पूर्ण जाँच एवं विधि के अनुरूप ही अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय पारित किये हैं। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है एवं अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के मु०न० 337/17 निर्णय दिनांक 9.2.18 एवं नायब तहसीलदार गंगापूर सिटी के मु०न० 55/15 निर्णय दिनांक 7.8.15 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

GM 30-9-19
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

